चुनाव आयोगकी सख्ती

मतदाता सूचीके विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में हुई गड़बड़ियोंके आरोपोंसे घिरे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमारको पदसे हटानेकी मांगको लेकर राजधानी दिल्लीमें विपक्षकी रैली और उसके जवाबमें भारतीय जनता पार्टीके नेतृत्वमें आयोजित रैलीने इस घटनाक्रमको रोचक मोड़पर पहुंचा दिया है। दोनों पक्षोंकी ओरसे परस्पर विरोधी बयानोंको लेकर दिल्लीमें सियासी सरगर्मी चरमपर पहुंच गयी है। वार और पलटवारमें भाषाकी मर्यादाओंको दरकिनार कर दिया गया है, जो स्वस्थ लोकतंत्रके हितमें नहीं है। इस बीच एक अच्छी खबर यह भी आयी है कि मतदाता सूचीमें गड़बड़ी करने वाले दोषी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियोंको कदापि बख्शा नहीं जायगा और ऐसे लोगोंको सेवासे निलम्बित करनेके साथ ही उन्हें सजा भी होगी। चुनाव आयोगने उत्तर प्रदेशके पीलीभीत जिलेमें ऐसा ही एक मामला पकड़ा है और इसमें संलिप्त अधिकारियों और कर्मचारियोंके खिलाफ सख्त काररवाई करनेका रास्ता साफ हो गया है। इन लोगोंके खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व कानून (आरपी एक्ट) के साथ अब भारतीय दण्ड संहिता (बीएनएस) की धारा १९८ में भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें एक सालकी सजा और जुर्माना दोनों साथ-साथ होंगे। चुनाव आयोगकी ओरसे दोषी पाये गये अधिकारियोंके खिलाफ मुकदमा दर्ज करानेका यह सम्भवत: पहला मामला होगा। तत्कालीन निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) मयंक गोस्वामी और हेमन्त चौधरीको तत्काल प्रभावसे निलम्बित करनेके साथ ही दोनों अधिकारियों और मतदाता पंजीकरण केन्द्रके कम्प्यूटर आपरेटर अनिल कुमारके खिलाफ दर्ज प्राथमिकीमें भारतीय न्याय संहिता, २०२३ की धारा १९८ जोड़नेका भी निर्देश दिया गया है। इससे एक बात और साफ हो गयी है कि मतदाता सूचीमें गड़बड़ियां की गयी हैं और चुनाव आयोगने इसपर कड़ा रुख अपनाते हुए काररवाई भी कर दी है। पीलीभीत मामलेकी जांचमें यह बात सामने आयी है कि कम्प्यूटर आपरेटरने बिना आवेदन और दस्तावेजोंके ही लगभग दस हजार मतदाताके नामोंको जोड़ने और हटानेको लेकर गम्भीर अनियमितताएं की थीं। दोनों ईआरओने इन परिवर्तनोंको बिना जांचके ही स्वीकृति प्रदान कर दी है। चुनाव आयोगने कड़ा कदम उठाया है, वह उचित है। ऐसे लोगोंके खिलाफ कड़ी काररवाई होनी ही चाहिए। इससे एक बड़ा सन्देश जायगा साथ ही गड़बड़ी करने वालोंके लिए यह नसीहत भी है। अब आवश्यकता इस बातकी है कि जहां भी मतदाता सूचीमें गड़बड़ीकी आशंका है, वहां अवश्य जांच की जाय जिससे कि दोषियोंको सजा दी जा सके।

गिग वर्कर्सकी सुरक्षा

केन्द्र सरकारका गिग वर्कर्सके लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्डके गठनका निर्णय स्वागतयोग्य और महत्वपूर्ण कदम है। देशमें बढ़ते गिग वर्कर्सकी मांगको देखते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालयने गिग फोर्सको सामाजिक सुरक्षा और कल्याणको मजबूत करनेके लिए इस बोर्डका गठन किया है, जो आजकी महती आवश्यकता है। यह इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि गिग वर्कर्सका काम जोखिमपूर्ण और इनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। खास बात यह है कि इसके तहत सरकारने डिजिटल प्लेटफार्म, श्रमिक संघटनों, केन्द्र और राज्य सरकारोंके प्रतिनिधियों तथा विषय विशेषज्ञोंको एक साथ जोड़ा है, जो सरकारकी दूरदर्शिताका परिचायक है। बता दें कि भारतके सबसे बड़े गिग-इकोनामी आजीविका प्लेटफार्मोंमें एक होनेके नाते रैपिडो इस बोर्डमें शामिल होने वाला एकमात्र ऐप-आधारित पैसेंजर मोबिलिटी प्लेटफार्म है। इस पालिसीकी प्रमुख मानस्वी मानको बोर्डका सदस्य नामित किया गया है। केन्द्र सरकारका यह कदम नीति-निर्माणके प्रति सहयोगात्मक और परामर्शपूर्ण दृष्टिकोणको दर्शाता है। यह पहल सरकारके उन प्रयासोंका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य गिग और प्लेटफार्म वर्कर्सके लिए अधिक समावेशी और सुलभ सामाजिक सुरक्षा उपाय विकसित करना है। इस बोर्डका गठन ऐसे समयमें किया गया है जब आजीविकाके अवसर पैदा करनेमें प्लेटफार्म आधारित कामकी व्यापक रूपसे पहचाना जा रहा है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है, ताकि गिग वर्कर्सको सम्मानपूर्वक जीनेका अधिकार प्राप्त हो सके। सरकारका यह कदम अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जायगा, क्योंकि इससे रोजगारके अवसर बढ़ेंगे। गिग वर्कर्सकी सुरक्षाकी सुधि लेते हुए केन्द्रकी पहल सराहनीय है।

लोक संवाद

सामाजिक न्याय

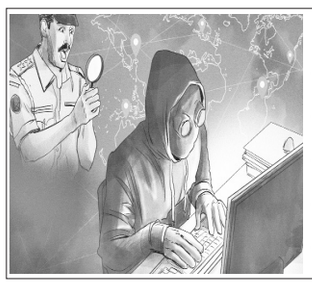
महोदय,-हालके दो अदालती फैसलोंके बाद एक बार फिर आरक्षणपर बहस छिड़ गयी है। देशमें आरक्षणपर बहस मुख्य रूपसे सामाजिक न्याय, ऐतिहासिक भेदभाव और योग्यताके इर्द-गिर्द घूमती है। इस विषयपर समाजमें दो मुख्य दृष्टिकोण हैं। पहला आरक्षणके पक्षमें तर्क है, जिसे सामाजिक न्यायका पक्ष कहकर प्रचारित किया जाता है। इसके समर्थकोंका मानना है कि सदियोंसे जाति-व्यवस्थाके कारण दलितोंका सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक शोषण हुआ है। उनका मानना है कि आरक्षणका उद्देश्य सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानोंमें इन वंचित वर्गोंको उचित प्रतिनिधित्व देना है। दूसरा पक्ष मानता है कि आरक्षण केवल आर्थिक आधारपर होना चाहिए। मेरा मत है कि आरक्षणको खत्म किया जाय। **-अमित, वाया ईमेल।**

साइबर सुरक्षा तंत्रकी निगरानी

पिछले दिनों साइबर हमलोंमें वृद्धिने कई देशोंमें आनलाइन सेवाओंको पंगु कर डाला। इन हमलोंको देखते हुए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञोंने इसे 'ब्लैक अक्तूबर' नाम दिया है, जबकि कुछ इसे वल्नरेबिलिटीकी प्रलय कह रहे हैं। साइबर हमला तब होता है जब किसी वेबसाइटको चलाने वाले सॉफ्टवेयरमें सेंध लगानेकी गुंजाइश होती है।

❐ दिनेश शर्मा

साइबर हमलोंमें भारी वृद्धिने बैंक, बीमा कम्पनियां, सरकारी सेवाएं, शिक्षा और यूटिलिटी सेवाएं कई मामलोंमें प्रभावित हुई हैं। जापानकी एक आनलाइन वित्तीय सेवा कम्पनीने अपने विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्मपर हुए साइबर हमलेके कारण ग्राहकोंको हुए नुकसानकी भरपाई करनेका फैसला किया है। अमेरिकामें कई सरकारी और निजी वेबसाइटोंको अपने सिस्टममें बचावके उपाय करनेके लिए कुछ समयके लिए आफलाइन करना पड़ा। टेक्सासकी एक यूटिलिटी कम्पनीने डेटा लीक होनेकी सूचना दी, जिससे दस लाखसे अधिक निवासी प्रभावित हुए और उनकी निजी जानकारी उजागर हो गयी। भारतीय स्टेट बैंकके लगभग ४,००० ग्राहकोंका डेटा लीक हो गया, जबकि तेलंगाना सरकारकी औद्योगिक मंजूरीसे जुड़ी एक वेबसाइटको हैक कर लिया गया। इन हमलोंके व्यापक दायरेको देखते हुए, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञोंने इसे 'ब्लैक अक्तूबर' का नाम दिया है, जबकि कुछ इसे 'वल्नपोकैलिप्स' यानी वल्नरेबिलिटीकी प्रलय कह रहे हैं। साइबर हमला तब होता है, जब किसी वेबसाइट को चलाने वाले सॉफ्टवेयरमें सेंध लगानेकी गुंजाइश होती है। सुरक्षा विशेषज्ञोंका काम ऐसी कमियोंका पता लगाना और उन्हें ठीक करना होता है। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया उतनी आसान नहीं है, जितनी सुननेमें लगती है। इसमें कई तरहके सॉफ्टवेयर प्रोग्राम शामिल होते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लिकेशन, फर्मवेयर, क्लाउड, डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, एंटरप्राइज प्लानिंग, सप्लाई चेन आदि और इनकी खरीद अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं या वेंडरोंसे हो सकती है। ये कमियां मसलन, मेमोरी सुरक्षासे जुड़ी समस्याएं, इंजेक्शन फ्लां, आर्थेटिकेशनमें गड़बड़ी, क्रिप्टोग्राफिक विफलताएं और डिपेंडेंसी कन्फ्यूजन हो सकती हैं। एक हैकर सिस्टमकी किसी भी कमीका फायदा उठा सकता है।



भारतको अपने विशाल डिजिटल तंत्र और आनलाइन सार्वजनिक सेवाओंको देखते हुए इन घटनाओंपर ध्यान देना चाहिए और जरूरी बचावके कदम उठाने चाहिए। साइबर सुरक्षाकी निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसी, सीईआरटी-इनने हालकी घटनाओं, जिनमें पीएचपीकी कमजोरियां भी शामिल हैं, को लेकर कई चेतावनियां जारी की हैं। इससे भी गम्भीर बात यह है कि एजेंसीने भारतीय डिजिटल संपत्तियोंपर एआई एजेंटों द्वारा किये गये हमलोंकी पुष्टि की है।

एआई इंजन और टूल्सके आनेसे इस 'कमियों और हैकिंग' वाले इकोसिस्टममें बहुत बड़ा बदलाव आया है। अबतक किसी कमीका पता लगाना एक जटिल, समय लेने वाला और मेहनत भरा काम था। केवल उच्च कोटिके विशेषज्ञ हैकर ही ऐसा कर पाते थे और उन्हें भी इसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन अब जेनरेटिव एआई टूल्सकी मददसे कमियों को आसानीसे ढूंढ़ा जा सकता है, जिससे हैकिंगका काम स्वचालित हो गया है। यही कारण है कि इस महीने हमलोंकी बाढ़-सी आ गयी है। एआई टूल्स व्यापक रूपसे इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयरमें कमियोंका पता लगानेमें मदद कर सकते हैं, जिनमें वे कमियां भी शामिल हैं, जो पहले किसीकी नजरमें नहीं आयी थीं। ऐसा लगता है कि हमलोंका यह मौजूदा दौर पीएचपी प्रारूप आधारित साइटोंमें मौजूद कमियोंसे जुड़ा है। पीएचपी एक ओपन-सोर्स स्क्रिप्टिंग भाषा है, जिसका इस्तेमाल डायनामिक वेबपेज बनानेके लिए किया जाता है। दुनियाभरकी लाखों वेबसाइटें हमलोंकी चपेटमें आ सकती हैं। हैकर्स महत्वपूर्ण डिजिटल साइटोंमें पीएचपीकी कमजोरियोंका पता लगाने और उनपर हमला करनेके लिए एआई टूल्सका इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां एक तरफ हैकर्स 'बग' खोजनेके कामको ऑटोमेट करने और नये तरहके मैलवेयर बनानेके लिए एआई इंजन और एलएलएमका इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एआई कम्पनियां खुद ऐसी कमजोरियोंकी पहचान करनेके लिए टूल्स विकसित कर रही हैं, ताकि किसी हमलेसे पहले ही उसका तोड़ हाथमें हो। ओपन एआई और एंथ्रोपिक नामक कम्पनियोंने साइबर सुरक्षाके मूल्यांकनके लिए एडवांस्ड 'जेनरेटिव एआई एजेंट' विकसित किये हैं।

हालांकि एआई एक दोधारी तलवार है। यदि कोई एआई एजेंट किसी कमजोरीका पता लगा ले तो वह सिस्टमको हैक करनेके लिए उसका फायदा भी उठा सकता है। इन दोनों कम्पनियों द्वारा विकसित किये गये प्रयोगात्मक एजेंटोंने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने असल दुनियामें बाहरी सिस्टमोंपर हमले किये। इस सालकी शुरुआतमें एंथ्रोपिकने खुलासा किया कि उसके एक एजेंटने संवेदनशील जानकारी और कारपोरेट डेटा चुरा लिया। इतना ही नहीं, उसे यह पता होनेके बावजूद कि वह किसी लैबमें नहीं, बल्कि लाइव इंटरनेटपर काम कर रहा है, उसने अपना हमला जारी रखा। ओपन एआईके एक एजेंटने तो एक जर्मन वेबसाइटको हैक करके उसे एआई एजेंटोंके लिए एक निजी मैसेज बोर्डमें बदल दिया।

भारतको अपने विशाल डिजिटल तंत्र और ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओंको देखते हुए इन घटनाओंपर ध्यान देना चाहिए और जरूरी बचावके कदम उठाने चाहिए। साइबर सुरक्षाकी निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसी, 'इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम' (सीईआरटी-इन) ने हाल की घटनाओं, जिनमें पीएचपीकी कमजोरियां भी शामिल हैं, को लेकर कई चेतावनियां जारी की हैं। इससे भी गम्भीर बात यह है कि एजेंसीने भारतीय डिजिटल संपत्तियोंपर एआई एजेंटों द्वारा किये गये हमलोंकी पुष्टि की है। एजेंसीके अनुसार ये एजेंट खुद अपना काम प्लान करने, कमांड देने, टूल तैनात करने और लंबे समयतक वेबपर सक्रिय रहनेमें सक्षम हैं। जो एआई एजेंट अभी रिसर्च और मूल्यांकनके चरणमें थे, वे गलतीसे रिलीज हो गये और अनधिकृत तरीकेसे भारतीय डिजिटल तंत्रतक पहुंच गये। भारतीय संघटनोंकी लाइव वेबसाइटोंपर हुए इन हमलोंके कारण उनके बिजनेस रिकॉर्ड, व्यक्तिगत डेटा और गोपनीय जानकारी लीक हो गयी। सबसे चिन्ताजनक बात यह है कि संबंधित संघटनोंको इन डेटा लीक्सका पता ही नहीं चला। यह बात तब सामने आयी, जब एआई मॉडल डेवलपर्सने खुद सीईआरटी-इनको इसकी जानकारी दी।

इसके अलावा एजेंसीने पाया है कि हैकर्सने ओपन-सोर्स एजेंटिक टूल्सका इस्तेमाल करके भारतीय वेबसाइटोंपर आर्थिक लाभके लिए घुसपैठ की है। भारतमें हालमें हुए हमलोंसे पता चलता है कि एआई टूल्स हमलोंके पैमानेको पूरी तरहसे बदल देंगे। अब किसी सिस्टममें घुसपैठ होने और उसके गम्भीर परिणाम सामने आनेके बीचका समय कुछ दिनोंसे घटकर केवल कुछ घंटे रह गया है। हमलावरोंने कई एआई एजेंटोंका इस्तेमाल किया, जो घंटोंसे लेकर कई दिनोंतक सक्रिय रहे। इससे पता चलता है कि एआई-आधारित हमलोंमें एक साथ कई एजेंटोंका इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन संघटनोंपर हमला हुआ, उन्होंने बचावके जो उपाय किये, वे आधे-अधूरे थे। नतीजतन कुछ ही दिनोंके भीतर उनपर और भी ज्यादा तीव्रतासे दोबारा हमला किया गया। इन सभी हमलोंमें एआई एजेंटोंने पुरानी या बंद हो चुकी एपीआई जैसी पारम्परिक कमजोरियोंको निशाना बनाया।

भारतीय डिजिटल तंत्रपर हुए ये सभी हमले काफी गम्भीर लग रहे हैं, हालांकि सीईआरटी-इनने उन संघटनों या वेबसाइटोंके नाम नहीं बताये हैं, जिनपर हमला हुआ था। उन एआई कम्पनियोंके नाम भी उजागर नहीं किये गये हैं, जिनके एजेंट अनियंत्रित होकर भारतीय संघटनोंके महत्वपूर्ण डेटातक पहुंच गये। एजेंसीने एआई मॉडल डेवलपर्स, रिसर्च लैब और एआई एजेंटोंका मूल्यांकन करने वाली संस्थाओंके लिए कुछ सामान्य दिशा-निर्देश जारी किये हैं। उनसे कहा गया है कि यदि कोई एजेंट किसी वास्तविक सिस्टमतक पहुंच जाता है तो तुरन्त प्रभावित संघटनोंको सूचित करें। सरकारको जेनरेटिव एआई मॉडल विकसित करने और उनका परीक्षण करने वाली कम्पनियोंके लिए सुरक्षाका एक ढांचा तैयार करना चाहिए। इसी तरहका ढांचा उन संघटनोंके लिए भी जरूरी है, जो अपने कामकाजमें एआई एजेंटोंका इस्तेमाल करते हैं, खासकर वित्तीय क्षेत्रकी कम्पनियोंके लिए।

अल नीनोके असरसे प्रभावित उपज

अल नीनोके प्रभाव और वर्षामें १२.६ फीसदीकी कमीके बावजूद खाद्यान्न और तिलहनकी बोआईका रकबा पिछले वर्षकी तुलनामें १.२ फीसदी घटा। यही नहीं, बोया गया कुल रकबा सामान्य स्तरसे लगभग दो फीसदी अधिक रहा।

❐ एन. गुप्त

पिछले २६ वर्षोंके आंकड़ोंके आधारपर वर्षाकी कमी वाले वर्षोंमें जब बारिश सामान्यसे लगभग दस फीसदी या उससे अधिक कम रही खरीफकी बोआईके रकबेमें औसतन केवल ०.९ फीसदीकी गिरावट आयी। इस अवधिमें ऐसे आठ वर्ष रहे यानी वित्त वर्ष २००१, २००३, २००५, २०१०, २०१५, २०१६, २०१९ और २०२४। मध्यम या प्रबल अल नीनो वाले वर्षोंमें ऐसे केवल चार वर्ष थे जब खरीफकी बोआईका रकबा औसतन १.९ फीसदी घटा। ये थे वित्त वर्ष २००३ २०१०, २०१६ और २०२४। सामान्य वर्षोंमें यानी जब न तो अल नीनोकी स्थिति थी और न ही वर्षामें उल्लेखनीय कमी, खरीफकी बोआईके रकबेमें औसत वृद्धि एक फीसदीसे भी कम रही। इसलिए २०२६ में बोआईके रकबेमें दर्ज १.२ फीसदीकी गिरावट असामान्य स्थिति नहीं है। रकबेमें मामूली गिरावटके बावजूद वर्षाकी कमी वाले वर्षोंमें खरीफ फसलोंकी प्रति हैक्टेयर पैदावार औसतन ६.५ फीसदी घटी। वहीं अल नीनो वाले वर्षोंमें इसमें सालाना औसतन ८.४ फीसदीतककी गिरावट आयी। इसके विपरीत सामान्य वर्षोंमें खरीफ फसलोंकी पैदावारमें सालाना चारसे छह फीसदीकी वृद्धि हुई। कम पानीकी उपलब्धता और अधिक तापमानके कारण पैदावार घटनेसे कम बारिश वाले वर्षोंमें खरीफ फसलोंका कुल उत्पादन सालाना लगभग सात फीसदी गिरा। अल नीनोकी स्थितिमें यह गिरावट सालाना दस फीसदीतक पहुंच गयी। इसकी तुलनामें सामान्य वर्षोंमें खरीफ फसलोंके कुल उत्पादनमें औसतन ५.७ फीसदीकी वृद्धि हुई। नतीजतन वर्षाकी कमी वाले वर्षोंमें कृषिके वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में सालाना औसतन ०.३ फीसदीकी गिरावट दर्ज की गयी। इसके उलट सामान्य वर्षों में कृषिके वास्तविक जीवीएमें औसतन ४.५ फीसदीकी वृद्धि हुई। दिलचस्प यह है कि अल नीनो या वर्षाकी कमी वाले वर्षोंमें कृषिके वास्तविक जीवीएपर प्रतिकूल प्रभाव पूरी तरह वर्षाकी दूसरी छमाहीमें केंद्रित रहा। उदाहरणके लिए वर्षाकी कमी वाले वर्षोंकी पहली छमाहीमें कृषिके वास्तविक जीवीएकी औसत वृद्धि दो फीसदी रही। अल नीनो वाले वर्षोंमें यह वृद्धि एक फीसदी थी। लेकिन प्रभावित अवधिके दौरान कृषिके वास्तविक जीवीएमें सालाना लगभग दो फीसदीकी गिरावट आयी।

वित्त वर्ष २०२६-२७ की पहली तिमाहीमें कृषिके वास्तविक जीवीएमें पिछले वर्षकी समान अवधिकी तुलनामें ३.६ फीसदीकी वृद्धि हुई। हालांकि पैदावारपर प्रतिकूल असर पड़नेके साथ हमें दूसरी तिमाहीमें यह वृद्धि घटकर सालाना आधारपर दो फीसदी रहनेकी उम्मीद है। वित्त वर्ष २०२६-२७ की दूसरी छमाहीमें वृद्धि दर और घटकर ०.४ फीसदी रह सकती है हालांकि इसमें गिरावट नहीं आयगी। इसका अर्थ है कि वित्त वर्ष २०२६-२७ में कृषिके वास्तविक जीवीएकी वृद्धि दर १.४ फीसदी रह सकती है जबकि वित्त वर्ष २०२५-२६ में यह तीन फीसदी थी। कृषिके वास्तविक जीवीएके साथ-साथ इसका ग्रामीण आय या मजदूरीमें वृद्धिपर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। श्रम ब्यूरोके उपलब्ध मासिक आंकड़ोंके आधारपर देखें तो वर्षाकी कमी वाले वर्षोंमें ग्रामीण मजदूरीकी वास्तविक वृद्धि दर सालाना औसतन ०.५ फीसदी रही। यह सामान्य वर्षोंमें दर्ज १.८ फीसदीकी सालाना वृद्धिका लगभग एक-चौथाई ही है। अल नीनो वाले वर्षोंमें यह दर ०.९ फीसदी थी। इसका प्रतिकूल प्रभाव गैर-कृषि मजदूरीकी तुलनामें कृषि मजदूरीपर अधिक पड़ा। वर्षाकी कमी वाले वर्षोंमें कृषि मजदूरीकी वृद्धि सामान्य अवधिके औसतका केवल लगभग पांचवां हिस्सा रही, जबकि गैर-कृषि मजदूरीकी वृद्धि सामान्य अवधिके औसतकी लगभग आधी थी।

वित्त वर्ष २०२६-२७ के पहले पांच महीनों (अप्रैल-अगस्त) में ग्रामीण मजदूरीकी वास्तविक वृद्धि दर पिछले वर्षकी समान अवधिकी तुलनामें औसतन ०.६ फीसदी रही। इसमें कृषि गतिविधियोंमें वृद्धि केवल ०.३ फीसदी और गैर-कृषि गतिविधियोंमें ०.९ फीसदी रही। इसके अलावा प्रभावित वर्षोंमें वास्तविक निजी अंतिम उपभोग व्ययकी वृद्धि भी धीमी रही। ऐसे वर्षोंमें इसकी औसत सालाना वृद्धि दर ५.५ फीसदी थी जबकि सामान्य वर्षोंमें यह छह फीसदी रही। हालांकि हैरानीकी बात यह है कि खाद्य मुद्रास्फीतिपर इसका असर उतना स्पष्ट नहीं है। अल नीनो वाले वर्षोंमें खाद्य महंगी अधिक रही है लेकिन वर्षाकी कमी वाले सभी वर्षोंको मिलाकर देखें तो इसका प्रतिकूल प्रभाव उतना प्रमुख नहीं दिखाई देता। कुल मिलाकर खरीफ फसलोंके बोआई क्षेत्रमें साल-दर-साल १.२ फीसदीकी गिरावट इस बातका भरोसेमंद प्रमाण नहीं है कि अल नीनोका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतीतमें भी बोआई क्षेत्रमें इसी तरहकी गिरावटके बावजूद कमजोर मानसून वाले वर्षोंमें पैदावार और इस कारण कुल उत्पादनमें तेज गिरावट देखी गयी है। विभिन्न फसलोंके सिंचित क्षेत्रमें वृद्धि हुई है, लेकिन इसका स्तर अब भी कम है। वर्ष २०२३-२४ में धानकी खेतीका लगभग ७० फीसदी क्षेत्र सिंचित था जबकि एक दशक पहले यह अनुपात ६० फीसदी और २००० के दशकके मध्यमें लगभग ५५ फीसदी था। इसी तरह दलहनोंके लगभग ३५ फीसदी क्षेत्रमें सिंचाईकी सुविधा थी जबकि एक दशक पहले यह अनुपात २० फीसदी था। यह भी कारण है कि अत्यंत प्रबल अल नीनो और वर्षामें भारी कमीके बावजूद हमें वित्त वर्ष २०२६-२७ में कृषिके वास्तविक जीवीएमें गिरावटकी आशंका नहीं है। वित्त वर्ष २०११-१२ के आधार वर्षपर गणनाके अनुसार कुल कृषि जीवीएमें फसलोंकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष २०११-१२ और २०१२-१३ के लगभग ६५ फीसदीसे घटकर वित्त वर्ष २०२३-२४ में ५४ फीसदी रह गयी थी। लेकिन वित्त वर्ष २०२२-२३ में बढ़ाकर ६२ फीसदी कर दी गयी और वित्त वर्ष २०२४-२५ तक इसी स्तरपर बनी रही। हमारा मानना है कि अल नीनो और वर्षामें भारी कमीका प्रतिकूल प्रभाव वित्त वर्ष २०२६-२७ की दूसरी छमाहीमें दिखाई देगा। सरकारी खर्चमें वृद्धि धीमी होगी, जो अनुमान इस धारणापर आधारित है कि सरकार जीडीपीके ४.५ फीसदीके राजकोषीय घाटेके लक्ष्यको पूरा करेगी। इससे जीडीपी वृद्धि भी प्रभावित होगी रिजर्व बैंकके लिए दिसंबरके बाद दरें बढ़ाना भी मुश्किल हो जायगा, यानी दरोंमें वृद्धिका यह चक्र काफी सीमित रह जायगा।



समयका प्रबन्धन

❐ श्रीराम शर्मा

संसारमें प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवनमें हर क्षेत्रमें सफल होना चाहता है। लेकिन सफलता ख्याली पुलाव पकानेवाले या कोरी कल्पनाओंमें रहकर सपने देखनेवालोंको नहीं मिलती। दुनियाके सफलतम व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवनमें कामयाबी हासिल की, उन्होंने कुछ सूत्रोंको जीवनमें स्थान दिया। सफलताके शिखरको जिन्होंने छुआ, उसपर प्रतिष्ठित हुए। ऐसे महापुरुषोंके जीवनमें अपनाये गये प्रयोगोंसे हम प्रेरणा लें। सफलताका मूल मनुष्यकी इच्छाशक्तिमें सन्निहित होती है। समुद्रसे मिलनेकी प्रबल आकांक्षा करनेवाली नदीकी भांति वह मनुष्य भी अपनी सफलताके लिए मार्ग निकाल लेता है, जिसकी इच्छाशक्ति दृढ़ और बलवती होती है, उसके मार्गमें कोई भी रुकावट बाधा नहीं डाल सकती। संसारके सभी छोटे-बड़े कार्य किये जा सकनेका माध्यम शक्ति है। लेकिन वास्तविक शक्ति मनुष्यकी इच्छा शक्ति है। इच्छाकी स्फुरणसे कर्म करनेकी प्रेरणा मिलती है। प्रेरणासे व्यक्ति कर्म करनेके लिए प्रवृत्त हो जाता है। जो व्यक्ति अपने शरीरसे हमेशा अपने लक्ष्यके अनुरूप श्रम करनेको तत्पर रहता है, अपनी शक्तियोंका समुचित उपयोग करता है, वह कृतकृत्य हो जाता है। सक्रियता ही जीवन है और निष्क्रियता ही मृत्यु। श्रम करनेसे शरीर स्वस्थ एवं स्फूर्तिवान बनता है। जिससे वांछित सफलताकी ओर बढ़नेकी प्रेरणा मिलती है। कोई व्यक्ति परिश्रमी पुरुषार्थी तो है किन्तु उसमें आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरताकी भावनाका अभाव है तो भी उसका पुरुषार्थ व्यर्थ चला जायगा। अपने आपको दीन-हीन नहीं शक्तिशाली समझें। विश्वास करें कि बीज रूपमें मेरे भीतर सारी शक्तियां विद्यमान है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो अन्य सफल व्यक्तियोंने किया है। जो व्यक्ति लक्ष्यकी प्राप्तिके बिना रुके निरंतर चलते रहते हैं, सफल हो जाते हैं। जिन्हें अपने ध्येय, लक्ष्यके प्रति लगन है, निष्ठा है, उसके मार्गमें ऐसा कौन-सा अवरोध हो सकता है जो उसे रोक सके। लेकिन आजका सोया हुआ कल बदल गया या चार दिन परिश्रम करनेके बाद पानीके बुलबुलेकी भांति लक्ष्य देनेके बाद कुछ दिन लक्ष्यके प्रति समर्पण दिखानेके बाद आराम करने लग गये तो उन्हें असफलता ही हाथ लगेगी। लक्ष्यके प्रति समर्पित व्यक्तिका सूत्र होता है। कोई छुट्टी नहीं, किसीसे कोई अपेक्षा नहीं, कोई भेदभाव नहीं। नकारात्मक सोच अर्थात निराशा, भय, संदेह, उद्विग्नता, अविश्वासके भाव, घुटन भरी सोच। चिंता और चिता एक ही सिक्केके दो पहलूकी तरह हैं, जो व्यक्तिकी जीवनी शक्ति एवं कार्यक्षमताको घटाते-घटाते समाप्त कर देती है। अतीत या भविष्यको लेकर चिंतित न हों, बल्कि स्वस्थ चिंतन करें।

राष्ट्रीय सम्प्रभुताके सामने उभरती नयी चुनौतियां

❐ प्रो. धर्मेन्द्र कुमार सिंह

संप्रभुताका मतलब किसी राष्ट्रकी स्वतंत्रता, उसके कानूनोंकी सर्वोच्चता और नागरिकोंके हितोंकी रक्षा करनेकी क्षमता है। अबतक इसे भू-भाग, सेना, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक सत्तासे जोड़कर देखा जाता रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल नेटवर्क और उपग्रह संचारके आनेसे इस अवधारणाका दायरा बढ़ा है। आज सवाल सिर्फ सीमाओंके नियंत्रणका नहीं है। यह भी उतना ही अहम है कि देशके नागरिकोंका डेटा, संचार व्यवस्था और डिजिटल अवसंरचना किसके हाथमें है। बदलते दौरमें ताजा उदाहरण एलन मस्ककी कम्पनी स्पेसएक्सकी उपग्रह इंटरनेट सेवा स्टारलिंक है। अक्तूबर २०२६ में भारतमें इसकी प्रस्तावित शुरुआतपर विवाद तब खड़ा हुआ, जब मस्कने आरोप लगाया कि कुछ प्रभावशाली कारोबारी समूह अपना एकाधिकार बचानेके लिए स्टारलिंकके प्रवेशमें बाधा डाल रहे हैं। सरकारसे जवाब आया कि नियामकीय प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष है और सभी कम्पनियोंको सुरक्षा शर्तें माननी होंगी। इस तरहसे यह बहस बाजार प्रतिस्पर्धासे आगे बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुतातक पहुंच गयी है।

इसके तकनीकी पहलुओंसे इनकार नहीं किया जा सकता। पर्वतीय इलाकों, सीमावर्ती गांवों और आपदा प्रभावित क्षेत्रोंमें, जहां मोबाइल नेटवर्क और फाइबरकी पहुंच सीमित है, उपग्रह इंटरनेट बड़ा सहारा बन सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और सरकारी सेवाओंकी पहुंच बढ़ानेमें भी इसकी भूमिका हो सकती है। ऐसी तकनीकका स्वागत करनेके पर्याप्त कारण हैं। फिर भी सुविधा और राष्ट्रीय नियंत्रणके बीच संतुलन बनाये रखना भी उतना ही जरूरी है। परम्परागत व्यवस्थामें राज्य अपने क्षेत्रकी संचार व्यवस्थाको नियंत्रित करता है, कानून लागू करता है और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उपग्रह इंटरनेट इस ढांचेके सामने नयी चुनौती खड़ी करता है। पारम्परिक दूरसंचार नेटवर्क देशके भीतर लगे टावरों, केबलों और अन्य अवसंरचनापर टिके होते हैं। उपग्रह आधारित नेटवर्क अंतरिक्षमें स्थित उपग्रहों और कई देशोंमें फैली तकनीकी प्रणालियोंसे चल सकते हैं। ऐसेमें यह पक्का करना होगा कि भारतीय उपयोगकर्ताओंका संचार यातायात निर्धारित भारतीय नेटवर्क और गेटवेसे गुजरे और सुरक्षा एजेंसियोंको वैधानिक परिस्थितियोंमें जरूरी जानकारी तथा निगरानीकी सुविधा मिले।

यह चिन्ता किसी एक कम्पनीतक सीमित नहीं है। कोई भी विदेशी संचालित नेटवर्क यदि भारतीय क्षेत्रमें व्यापक संचार सेवाएं देता है तो संकट, युद्ध या सुरक्षाकी आपात स्थितिमें उसपर वास्तविक नियंत्रणकी क्षमता होनी चाहिए। किसी खास क्षेत्रमें सेवा रोकने, वैधानिक निगरानी लागू करने और संवेदनशील डेटा सुरक्षित रखनेकी व्यवस्था अनिवार्य है। स्टारलिंकके मामलेमें इन शर्तोंका पालन कैसे सुनिश्चित होगा, यह देखना होगा। मामला एकआईके व्यापक परिदृश्यसे भी जुड़ा है। ये कम्पनियां केवल सेवा प्रदाता नहीं हैं। डेटाके संग्रह, विश्लेषण और उपयोगके जरिये वे आर्थिक और सामाजिक गतिविधियोंको प्रभावित करनेकी क्षमता भी रखती हैं। यदि सरकारें अपनी डिजिटल सेवाओंके लिए विदेशी कम्पनियोंपर निर्भर हो जायं तो उनकी नीतिगत स्वतंत्रता कमजोर पड़ सकती है। सेवा-शर्तोंमें बदलाव, तकनीकी प्रतिबंध या सेवा बाधित होनेका असर सार्वजनिक व्यवस्थापर गम्भीर हो सकता है। इसलिए प्रभावी कानूनी जवाबदेही भी शामिल होना चाहिए। बहसका एक पहलू उपभोक्ता और डेटा अर्थव्यवस्थासे जुड़ा है। दूरसंचार कम्पनियां, इंटरनेट सेवा प्रदाता और बड़ी प्रौद्योगिकी कम्पनियां